ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन अधिनियम 1980

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम में ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 लागू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन कितने ठेकेदारों ने लाइसेंस प्राप्त किए हैं और इस सम्बन्ध में जिन स्थानों के लिए लाइसेंस जारी किए गए है उनके क्या नाम है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव विरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा

*858. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर बहुत सी अनधिकृत कालोनियां बना ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध सरकारी स्थान (बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ग) अनधिकृत कब्जे वाली ऐसी भूमि का ब्यौरा क्या है और क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं । तथापि, कतिपय क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत दखल के मामले हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस बारे मे कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जो मामले उनके नोटिस में आते है, कानून के अन्तर्गत उन पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

Shortage of store in Telecom. Circles

*859. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to lay a statement showing:

(a) whether there is an acute shortage of stores with the Telcom. Circles in the country resulting in the slow pace of telecom development and accounting for most of the projects being held up as also for deterioration in the services;

(b) if so, the position of stores as on 31st March, 1981 in each one of the Telecom. Circles;

(c) the reasons for this shortage and the steps taken to overcome this shortage; and

(d) whether powers for local purchase of minor items would be vested at the Sub-Divisional level so as to ensure immediate removal of faults and guarantee efficient